BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 25th February, 2015 | No. 4

माननीय श्री नीतीश कुमार ने चौथी बार संभाली बिहार की बागडोर

माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने दिनांक 22 फरवरी, 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उनके मंत्रीमंडल के सभी मंत्रियों को बिहार के समस्त व्यवसायियों एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।

हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा।

बिहार के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सद्प्रयासों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर संभव सहयोग के लिए कृत संकल्पित है।

– ओ० पी० साह, अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

बिहार मंत्रीमंडल

(मंत्री और विभाग)

❖ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार	:	सामान्य प्रशासन, गृह समेत वे सभी विभाग, जो किसी को आवंटित नहीं है।
❖ विजय कुमार चौधरी	:	जल संसाधन
❖ विजेन्द्र प्रसाद यादव	:	वित्त एवं वाणिज्य-कर
❖ रमई राम	:	परिवहन
❖ श्रवण कुमार	:	ग्रामीण कार्य व संसदीय कार्य
❖ पी० के० शाही	:	पर्यावरण एवं वन, योजना एवं विकास
❖ ललन सिंह	:	पथ निर्माण
❖ दामोदर रावत	:	भवन निर्माण
❖ श्याम रजक	:	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
❖ रंजू गीता	:	गन्ना उद्योग
❖ नरेन्द्र नारायण यादव	:	राजस्व एवं भूमि सुधार
❖ लेसी सिंह	:	समाज कल्याण
❖ विनोद यादव	:	पंचायती राज
❖ अवधेश प्रसाद कुशवाहा	:	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध
❖ मनोज कुमार सिंह	:	लघु जल संसाधन
❖ बीमा भारती	:	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
❖ जय कुमार सिंह	:	सहकारिता
❖ राम लषण राम 'रमण'	:	खनन
❖ बैद्यनाथ सहनी	:	पशु एवं मत्स्य संसाधन
❖ नौशाद आलम	:	अल्पसंख्यक कल्याण
❖ रामधनी सिंह	:	स्वास्थ्य
❖ जावेद इकबाल अंसारी	:	पर्यटन
❖ दुलाल चंद गोस्वामी	:	श्रम संसाधन

(साभार : प्रभात खबर, 23.02.2015)

पुलिस महानिदेशक के साथ चैम्बर की बैठक

• पटना में जल्द ही लगेगा पुलिस इंफोर्मेशन कियोस्क • पटना में पुलिस कमिश्नरी की स्थापना का प्रस्ताव
• और संवेदनशील बनेगी पुलिस • चैम्बर के सुझावों पर होगा विचार : डी०जी०पी०

बैठक को संबोधित करते श्री कुन्दन कृष्णन, आईजी (मुख्यालय), उनकी दाँयीं ओर क्रमशः श्री पी० के० ठाकुर, डीजीपी, श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री एम० एन० बरेरिया, उपाध्यक्ष एवं डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 12 फरवरी, 2015 को श्री पी० के० ठाकुर, पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारीगण भी मौजूद थे।

अपने संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि महोदय, आप हमारे इस बात से सहमत होंगे कि पुलिस की पूरी शक्ति भी अपराध का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर सकती जब तक कि स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिले। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार को व्यापार एवं उद्योगों के विकास के माध्यम से ही पैदा किया जा सकता है। आप हमें सुरक्षा दीजिए, उचित वातावरण दीजिए, उचित सम्मान दीजिए और बदले में हम राज्य में आर्थिक उत्थान एवं समृद्धि लायेंगे जिससे अपराध की दर स्वतः घटेगी। राज्य के सम्पूर्ण विकास में पुलिस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज होता है।

किसी भी काल में अपराधमुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है परन्तु जिस समाज में अपराधी पर अंकुश हो अर्थात अपराधी भययुक्त हों, उस समाज की सर्वत्र तारीफ होती है तथा समाज में भयमुक्त वातावरण रहता है।

पिछले कुछ घटनाओं में पुलिस प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्यों का जिक्र करते हुए श्री साह ने कहा:-

1. दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के रात में सीतामढ़ी के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री यतीन्द्र खेतान की अपराधियों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। हमें सूचना मिली, हमने 1 जनवरी 2015 को पुलिस महानिदेशक महोदय से उस घटना के विषय में अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक महोदय ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं इस काण्ड की मोनेटरिंग कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। हमें यह कहते हुए संतोष है कि पुलिस महानिदेशक महोदय के आश्वासन के आलोक में उस काण्ड के सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

2. गोविन्द मित्रा रोड के बैद्यनाथ फर्मा में हुई चोरी की घटना का भी उद्भेदन पटना पुलिस प्रशासन ने शीघ्र करके रूपयों की बरामदगी की।

इस तरह की घटनाओं में त्वरित उद्भेदन से व्यवसायी समाज में आत्म-विश्वास बढ़ता है साथ ही अपराधियों का मनोबल गिरता है।

अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो, इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में पुलिस महानिदेशक का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर आकृष्ट कराते हुए श्री साह ने कहा कि:-

- पटना जिला की शहरी आबादी अनुमानतः 30 लाख तथा ग्रामीण आबादी 40 लाख है। इस तरह पटना जिला की कुल आबादी अनुमानतः 70 लाख है। हमारे यहाँ Metropolitan Act लागू हो चुका है जिसके अनुसार 10 लाख से उपर की आबादी वाले शहर को Metropolitan City का दर्जा मिल गया है। Metropolitan City में Police Commissionerate System लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पटना में Metropolitan Court की भी स्थापना की जानी चाहिए। शहरी इलाके के लिए अलग Urban Force का गठन होना चाहिए। जिस तरह पश्चिम बंगाल में कोलकता पुलिस और महाराष्ट्र में मुम्बई पुलिस का गठन किया गया है और यह राज्य पुलिस बल का अंग होते हुए भी सिर्फ शहरों में पुलिसिंग का काम करता है।
- Commissionerate of Police को अन्य Metro Town की तरह Commissionerate of Police का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा शहर के कानून व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके। इसके अतिरिक्त श्री साह ने अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण, बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना, दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग, अपराध संवेदन स्थानों पर सघन पुलिस पेट्रोलिंग, व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि, नियमित बैठक की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित सुझाव दिये।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि राजधानी सहित पूरे सूबे में अपराधी पकड़े जा रहे हैं फिर भी आपराधिक वारदात थम नहीं रहे हैं, यह चिन्तनीय है।

बी०सी०डी०ए० के अध्यक्ष श्री पी० के० सिंह ने सीमामढ़ी में त्वरित कार्रवाई द्वारा दवा व्यवसायी की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि कोई अपराधी लल्लू मियाँ है, वह अभी तक फोन पर दवा व्यवसायियों को धमकी दे रहा है, वो अभी तक पकड़ा नही गया है। गोविन्द मित्रा रोड में दवा की बड़ी मंडी है। वहाँ पर 24 घंटे पुलिस बल रहे। इसके अतिरिक्त दवा व्यवसायियों को आत्मरक्षार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर आर्म लाईसेंस दिया जाए।

श्री प्रदीप जैन ने कहा कि पटना शहर में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध हेतु अधिसूचना जारी हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि बिना लाईसेंस वाले मांस न बेचे, इस ओर पुलिस ध्यान दे।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने पुलिस अनुसंधान के अच्छे रिजल्ट की तारीफ करते हुए कहा कि चैम्बर के सामने सब्जी वालों के द्वारा रोड का अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे काफी परेशानी हो रही है। इसे महेन्द्रु घाट तक बढ़ा दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक पुलिस आउट पोस्ट भी स्थापित करने का अनुरोध किया।

पाटलीपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने कहा कि हाल के महिनों में राजधानी में सेंधमारी की घटनाएँ काफी बढ़ गई हैं। एक व्यवसायी मुन्ना साह की हत्या कर दी गयी है। बाकरगंज में 350 दुकानें है जिसमें ज्वेलर्स की दुकानें अधिक हैं वहाँ CCTV कैमरे की व्यवस्था करायी जाए। साथ ही 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग का भी अनुरोध किया।

श्रीमती सुष्मा साहू ने कहा पुलिस की गाड़ियाँ चौक-चौराहे में लगी रहती है, जिससे परेशानी होती है, थोड़ा किनारे लगाने का अनुरोध किया। एक पूर्व पार्षद के भाई की हत्या एवं दरभंगा में रेखा झा के पति के अपहरण की तरफ ध्यान दिलाने के साथ कहा कि थानों में अधिकारी का व्यवहार भी काफी दुखद है।

बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन के सदस्य श्री अमित मुखर्जी ने ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार की जरूरत बताई और कहा कि उन दो पहिया वाहन वालों पर कड़ाई करने की जरूरत है जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री उत्पल सेन, श्री सुबोध जैन आदि ने भी ट्रैफिक से संबंधित समस्याएँ बताई एवं सुझाव दिए।

सदस्यों की समस्याओं एवं सुझावों को सुनने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र राणा ने कहा कि पटना में पुलिस कमिश्नरेट स्थापना का प्रपोजल है, इसके बारे में महानिदेशक महोदय जानकारी देंगे। बेगलुरू की तरह राजधानी में भी कियोस्क सिस्टम की तरह अब FIR दर्ज किये जाएँगे। ए०टी०एम० की तरह सार्वजनिक स्थानों पर मशीन लगे रहेंगे जहाँ कोई भी नागरिक प्राथमिकी का आवेदन दे सकता है। ये मशीनें पुलिस मुख्यालय से जुड़ी रहेंगी और उसे संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। सरकार की सहमति मिलने तक यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू रहेगा। इस प्रणाली को चालू करने में व्यवसायियों का सहयोग मांगा। उन्होंने Civil Society के लोगों को Resident Welfare Association बनाने की आवश्यकता बताई। किरायेदार/कर्मचारी के सत्यापन के अभियान में सदस्यों से सहयोग की भी अपील की।

जोनल आई०जी० श्री ए० के० अम्बेदकर ने चैम्बर को पुलिस कमिश्नरेट का प्रस्ताव देने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि राजधानी के ग्रेटर पटना होने की स्थिति में Police Commissionarate काफी उपयुक्त होगा। पुलिस अधिकारियों को जनता से संवाद के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, आप अपने शिकायत ईमेल से भेज सकते हैं। पटना जिला पुलिस ने पिछले साल 2.5 करोड़ दंड राशि वसूल किया। उन्होंने बताया ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हो रही है। 27 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें कैमरा भी रहेगा जो ट्रैफिक लोड के अनुसार सिग्नल देगा। अप्रील तक यह चालू हो जाएगा। उन्होंने व्यवसायियों से प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरा लगाने का अनुरोध किया।

आई०जी० हेडक्वार्टर श्री कुन्दन कृष्णन ने कहा कि वन-वे की व्यवस्था तब तक लागू नही हो सकता, जब तक सारे पुल-पुलियों का निर्माण नहीं हो जाए। पटना म्युनिशपल कारपोरेशन को नेशनल भेंडर एक्ट के तहत् लाईसेंस देकर भेंडर जोन चिन्हित करना है। पटना में ऑटो 25-30 हजार है। प्रतिदिन ट्रॉसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑटो का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यह भी ट्रैफिक लोड को काफी बढ़ा रहा है। जब तक नीति निर्धारण नहीं होगा पुलिस कुछ नहीं कर पायेगी।

पुलिस महानिदेशक श्री पी० के० ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अर्से बाद चैम्बर की बैठक में आया हूँ। काफी समस्याओं से रू-ब-रू होने का अवसर मिला। चैम्बर की ओर से जो सुझाव आये हैं उन पर ध्यान दूँगा। बिहार की आबादी 11 करोड़ है। इस स्थिति में 55-60 हजार पुलिसकर्मी हैं। इस बार 11500 पुलिस की बहाली होगी। मेरी कोशिश होगी की बिहार में पुलिसकर्मी राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो।

श्री ठाकुर ने कहा कि पुलिस पीड़ितों की बात सहानुभूतिपूर्वक सुनें और सही कार्रवाई करें साथ ही व्यवहार अच्छा होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कमिश्नरेट की धारणा पुरानी है, 1980 में थी। जनवरी 2015 में इसके लिए प्रस्ताव सरकार को दिया है। पटना पुलिस को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता रही है। पटना में पुलिस के कार्यों की अधिकता के फलस्वरूप तीन एस० पी० तैनात किए गये हैं। उन्होंने कहा कि अपराध में मजबूत साक्ष्य जुटाए जायें, ताकि असली अपराधी को सजा हो सके। इससे पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा। हाई-वे पेट्रोलिंग से भी काफी फायदा हुआ है। मोबाईल पुलिस को गाड़ियों से पेट्रोलिंग के दौरान पैदल गलियों में भी चक्कर लगाना होगा ताकि अपराधियों में भय पैदा हो सके। जमानत पर छूटने वाले अपराधियों पर भी नजर रखें। प्रत्येक जिले में मोबाईल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अभी पटना, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पुर्णिया में विज्ञान प्रयोगशाला है। श्री ठाकुर ने कहा कि आम नागरिक को वाहन चेकिंग में परेशान करने से बेहतर है कि पुलिस विवेक का उपयोग कर धर-पकड़ करे।

सीतामढ़ी कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का पुलिस महानिदेशक से परिचय कराते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में बीसीडीए के अध्यक्ष श्री पी० के० सिंह।

श्री ठाकुर ने अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों और व्यवसायिक क्षेत्रों के पास गहन चौकसी करने की हिदायत भी दी। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि अपराध की जानकारी होने पर हमे अविलम्ब सूचित करें।

उक्त अवसर पर डी०आई०जी० श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, सीटी एस०पी० (मध्य) श्री चन्दन कुशवाहा, सीटी एस०पी० (पश्चिम) श्री राजीव मिश्रा, सीटी एस०पी० (पूर्वी) श्री सुधीर कुमार पोडिका, ग्रामीण एस०पी० श्री हर किशोर राय, एस०पी० (रेल) श्री प्रकाश नाथ मिश्रा, एस०पी० ट्रैफिक श्री पी० के० दास, उपाधीक्षक (ट्रैफिक) श्री विजय कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकरनाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी सहित बिहार के कई संगठनों के प्रतिनिधि, चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

फोटोग्राफी के प्रति समर्पित थे कृष्ण मुरारी

रामजी मिश्र मनोहर मीडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में दिनांक 11 फरवरी 2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में फोटो जर्नलिस्ट कृष्ण मुरारी किशन को श्रद्धांजलि दी गई।

इस मौकें पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय, कुम्हारार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, सांसद अश्विनी चौबे, भाजपा नेत्री डॉ. किरण घई, चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह, पूर्व अध्यक्ष युगेश्वर पाण्डेय, बिहार जैन संघ के अध्यक्ष तनसुख लाल वैद, फाउंडेशन के सचिव प्रदीप जैन, ज्ञानवर्द्धन मिश्र संयुक्त सचिव पंकज वत्सल सहित अन्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कहा कि कृष्ण मुरारी किशन फोटोग्राफी के प्रति ताउम्र समर्पित रहे। परिस्थितियाँ चाहें जो भी हों, घटनास्थल पर उनकी हाजिरी रहती थी। कभी तनाव उन्हें छू नहीं पाया। मुस्कुराहट के साथ फोटोग्राफी की बारीकी, नई तकनीक के साथ बिहार की फोटोग्राफी को उन्होंने देश दुनिया तक पहुचाया। नई पीढ़ी के छायाकार हमेशा उनसे सबक लेते रहेंगे। चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि हम लोग केंद्र सरकार की ओर से कृष्ण मुरारी किशन को पद्मश्री देने का प्रस्ताव भेजेंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.2.2015)**

'इंडियन इकोनॉनी लूकिंग फॉरवर्ड' विषय पर के. एन. सहाय स्मृति व्याख्यानमाला में बोले यशवंत सिन्हा

प्रदेश के विकास को आगे आयें बिहारी

व्याख्यानमाला में मंचासीन (बाँयें से दाँयें) श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष, पूर्व वित्त केन्द्रीय मंत्री श्री यशवन्त सिंहा एवं श्री रवि नन्दन सहाय।

के. एन. सहाय शहरी विकास संस्थान द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2015 को आयोजित 14वें के. एन. सहाय स्मृति व्याख्यानमाला में पूर्व केन्द्रीय विदेश व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि के. एन. सहाय जिंदादिल इंसान थे। आज एहसास नहीं हो रहा है कि उनकी स्मृति सभा में बोल रहे हैं। आज का दिन उनके जीवन आदर्श को याद करने व उनके पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। व्याख्यानमाला में "इंडियन इकोनॉमी-लूकिंग फॉरवर्ड" विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को सभी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। श्री सिन्हा ने देश में राज्य, केन्द्र व राज्य के बीच असमानता को दूर करने पर जोर देते हुए अगला बजट तैयार किये जाने की बात कही। अगले बजट में उन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जो विकास के लिए सार्थक हों। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बिहारियों को आगे बढ़ना होगा। बिहार को ही इसके लिए कमर कसना पड़ेगा। एक बार बिहारी खुद को संभाल लें तो कोई विकास को रोक नहीं सकता।

व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि के. एन. सहाय चार बार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष रहे। पटना नगर निगम के महापौर रह कर उन्होंने जनता की सेवा की। श्री साह ने आगे कहा कि विश्व के बाजार में भारतीय उत्पाद पहुँच रहा है मगर बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। उन्होंने प्रदेश में उद्योग, आर्थिक व सामाजिक विकास में के. एन. सहाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्री यशवंत सिन्हा से प्रदेश के विकास की पहल करने का अनुरोध किया।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि के. एन. सहाय के निधन से जो रिक्तियां हुई वह अब तक नहीं भरी जा सकी। के. एन. सहाय के पुत्र श्री रविनंदन सहाय ने अतिथियों का स्वागत किया और के. एन. सहाय स्मारक व्याख्यानमाला के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पद्मश्री डॉ० नरेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन

डॉ० नरेन्द्र प्रसाद अभिनन्दन समिति की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 21 फरवरी, 2015 को सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉ० नरेन्द्र प्रसाद को पद्मश्री मिलने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। मंच संचालन पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने किया।

अपने स्वागत उद्बोधन में श्री ओ० पी० साह ने कहा कि डॉ० प्रसाद राज्य के गिने-चुने सर्जनों में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1989 से 1992 तक राज्य के प्रमुख अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह कर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि डॉ० नरेन्द्र प्रसाद एक ऐसे सख्सियत हैं कि इनको पदमश्री का सम्मान मिलना उस सम्मान का भी सम्मान है।

समारोह के संयोजक श्री युगेश्वर पाण्डेय ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि डाक्टर को हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए क्योंकि रोगी की आधी बीमारी डाक्टर के व्यवहार से ही दूर हो जाती है और यह सारा गुण डॉ० नरेन्द्र प्रसाद में है। उन्होंने कहा कि हम सभी राज्य सरकार से मांग करेंगे कि डॉ० नरेन्द्र प्रसाद को पद्मभूषण का सम्मान मिलना चाहिए।

पद्मश्री डॉ० नरेन्द्र प्रसाद ने उन्हें सम्मान देने के लिए राज्य के सभी उद्यमियों एवं व्यवसायियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी से उपर राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सामाजिक सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो भी उपलब्धियाँ हैं, वह समाज की देन है इसलिए मैं समाज का सदैव ऋणी हूँ।

पद्मश्री डॉ० आर० एन० सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त श्री आई० सी० कुमार एवं श्री आर० यू० सिंह, श्री पी० के० सिंह, श्री प्रदीप कुमार सिंह ने भी डॉ० नरेन्द्र प्रसाद के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किये।

पद्मश्री डॉ० नरेन्द्र प्रसाद का पुष्प-गुच्छ देकर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, पद्मश्री डॉ० आर० एन० सिंह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, विनोद कृष्ण कानोरिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं अन्य।

समारोह में श्री एल० एन० रस्तोगी, श्री दिलजीत खन्ना, श्री एन० के० ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन के साथ-साथ काफी संख्या में उद्यमी, व्यवसायी एवं प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समरोह सम्पन्न हुआ।

पटना जंक्शन से 9 ट्रेनें हटाने पर भड़के यात्री

पटना जंक्शन से नौ प्रमुख ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों से खोलने के रेलवे के फरमान से यात्रियों में आक्रोश है। पटना जंक्शन से खुलने वाली जितनी ट्रेनों को दानापुर से खोलने का निर्णय लिया गया है उसमें 90 फीसद छात्र या व्यापारी ही यात्रा करते हैं।

यात्रियों को इस निर्णय से असुविधा होगी यह तो सही है लेकिन पटना जंक्शन की स्थिति ही ऐसी हो चुकी है कि यह निर्णय कई मायनों में उचित है। आउटर पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आवाजाही के लिए प्लेटफार्म पर जगह नहीं रहती। बात एक ही है अगर पटना जंक्शन का विस्तार हो तो बढ़िया होगा। यात्रियों को राहत भी मिल जाएगी। – **ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : दैनिक जागरण, 6.2.2015)

सब्सिडी की कम मांग होने पर बढ़ेगी उद्योगों की संख्या

बिहार राज्य योजना पर्षद के मुख्य सलाहकार आलोक कुमार सिन्हा ने कहा है कि 2016 में नए सिरे से औद्योगिक नीति बनाने का प्रस्ताव है। इस नीति में सब्सिडी लेने के बजाए उद्योगपति उन प्रक्रियाओं की बात करें जिससे बिहार में उद्योगों का जाल बिछ सके। बिहार में उद्योगों का जाल तभी बिछ सकता है जब सब्सिडी आधारित औद्योगिक नीति की मांग कम से कम हो।

मंगलवार को कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की वार्षिक बैठक में 'बिहार में निर्माण' विषय पर हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार से अनुदान मिलने के बावजूद कुछ उद्योग चालू नहीं हो सके। जमीन की समस्या बताने वाले उद्योगपतियों को यह भी याद रखना चाहिए कि बंद होने के बावजूद सैकड़ों एकड़ जमीन अब भी उनके कब्जे में है। जो उद्योग नहीं चल रहे हैं, उस जमीन को वापस किया जाना चाहिए। सीआईआई बिहार चैप्टर के अध्यक्ष एसपी सिन्हा ने कहा कि उद्योगों के लिए शासन-प्रशासन के स्तर पर माइंडसेट में बदलाव जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण व सस्ती बिजली चाहिए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.2.2015)**

आभूषण उद्योग को हस्तशिल्प का दर्जा

सोना-चांदी उद्योग को भी हस्तशिल्प का दर्जा प्राप्त हो गया है। हस्तशिल्प उद्योग के नियमों का लाभ अब आभूषण विक्रेताओं को भी मिलेगा। जो ज्वैलर सोने- चांदी के आभूषण बनाने में मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें हस्तशिल्प मंत्रालय से पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिसके आधार पर ज्वैलर हस्तशिल्प उद्योग में शामिल होने का फायदा उठा सकेंगे। ज्वैलरी उद्योग को हस्तशिल्प उद्योग का दर्जा अदालत के आदेश पर दिया गया है।

हस्तशिल्प की सूची में 32 उत्पादों में सोने-चांदी को भी शामिल किया गया है। सोने-चांदी के आभूषण में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो हाथ से बनाए जाने वाले यानी हस्तशिल्प उद्योग के उत्पादों में देखने को मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले सोने-चांदी के आभूषण हस्तशिल्प के दायरे में आते हैं। परंपरागत ज्वैलरी को बनाने वाले कारीगरों को हमेशा इसकी शिकायत रहती थी कि वह बेहतरीन हस्तकला का परिचय देते हैं लेकिन सरकार उनकी इस कारीगरी को हस्तशिल्प में शामिल नहीं करती है। इस मुद्दे को ज्वैलर अदालत में ले गए। उच्चतम न्यायालय ने सोने-चांदी के आभूषण को हस्तशिल्प उद्योग की परिभाषा के अंदर पाया और इसी आधार पर सोने-चांदी उद्योग को हस्तशिल्प उद्योग का दर्जा देने का आदेश दिया।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.2.2015)

पटना सिटी का बल्ब उद्योग गिन रहा है अंतिम सांसें

वर्ष 2017 तक देशभर में टंगस्टन बल्ब के उद्योग को बंद कर देने के केंद्र के फैसले से पटना सिटी का बल्ब उद्योग खत्म होने की कगार पर है। यहाँ की 98 लघु व बड़ी कंपनियां बल्ब उत्पादन से जुड़ी हैं। सभी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

पटना सिटी की बल्ब कंपनियों के बंद होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10 से 15 हजार लोगों की रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो सकती है। इस स्थिति से बचाने के लिए पटना सिटी के बल्ब उद्योग को एलईडी लाइट उद्योग में बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए केंन्द्र और राज्य सरकार दोनों से सहयोग मिलना जरूरी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.2.2015)

महिला उद्यमियों को आसानी से नहीं मिलता कर्ज

भारत में पिछले दो दशक के दौरान अप्रत्याशित आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन इस दौरान अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। इसके साथ ही उन्हें कर्ज मिलने में भी परेशानी होती है।

इसमें कहा गया है कि भारत में महिला उद्यमियों के मामले में 73 प्रतिशत मामलों में कर्ज उपलब्ध नहीं होता। इस मामले में एक बड़ी चुनौती यह है कि महिलाएं अपने व्यावसाय का पंजीकरण नहीं करा पाती हैं क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी जटिल और ऊँची लागत वाली है।

श्रमबल में महिलाओं की 27 प्रतिशत भागीदारी के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे कम भागीदारी वाले देशों, में है। कर्ज की सरल उपलब्धता और उत्पादों के लिए विपणन का बेहतर मंच बनाकर महिल उद्यमियों को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.2.2015)**

USE OF CREDIT RATINGS FOR SMEs

The Small and Medium Enterprise (SME) Sector gains prominence in our economic framework because of its critical role in the growth and development of the economy especially in terms of economic growth and job creation. India's growth trajectory in coming times would to a large extent be defined by the strength and pace of growth of the SME sector, Not only does the sector promote entrepreneurship and innovation, it provides the necessary inputs/support to the large industries,. These entities are vital for the growth of the manufacturing sector of the country and are being relied upon for raising the share of India's manufacturing sector from the.

(Details : SME WORLD February, 2015)

REITS IN INDIA : BOON FOR SMALL INVESTERS

The real estate sector of India presently contributes about 5% to the national GDP, is the second largest employer after the agricultural, and is growing rapidly with a compound annual growth rate (CAGR) of over 11%. Currently, the real estate sector of India is the fourth biggest in respect of FDI inflows (the Government of India has allowed FDI upto 100% in the development projects for township and settlements) and is constantly growing to reach the expected level of us $ 650 billion by 2020.

(Details : SME WORLD February, 2015)

बिना एटीएम कार्ड के घर पर मिलेंगे रुपए

पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिना एटीएम कार्ड के भी बैंक खाते से रुपए निकाले जा सकेंगे। वह भी घर बैठे। इसके लिए किसी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बैंक के उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। आधार नम्बर पर आधारित यह सुविधा नए वित्तीय वर्ष से ही शुरू होने वाली है।

इसके लिए सभी बैंक अपने एजेंट नियुक्त करेंगे जिनकी जानकारी ग्राहकों को बैंक के माध्यम से मिल जाएगी। जरूरत पड़ने पर इन्हें घर भी बुलाया जा सकेगा। इनके पास एक माइक्रो एटीएम मशीन रहोगी जो आधार और बायोमेट्रिक तकनीक पर ग्राहकों की वैधता को चेक करेगा। इस माइक्रो एटीएम से डिपॉजिट, निकासी, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट की सुविधा मिलेगी।

20 लाख लोगों को मिलेगी सुविधा : इस योजना से पटना के 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सीधा लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक (बिहार-झारखंड) मनोज कुमार वर्मा के अनुसार बिहार में वित्तीय समावेशन पाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा।

बैंकों को भी होगा फायदा : इसके लागू होते ही बैंकों के ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेहद कम हो जाएंगे। एटीएम स्थापित और उसे संचालित करने का खर्च अभी क्रमश: 5 लाख व 60 हजार महीना है। जबकि इन मशीनों की कीमत महज 10से 15 हजार है। बैंक इस पूरी लागत से बच जाएंगे। बिजनेस कॉरसपांडेंट को विशेष व्यवरथा के तहत अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.2.2015)**

उद्योग खुद संभाले विदेशी मुद्रा का जोरिवम: आरबीआई

भारतीय कंपनियों द्वारा बगैर हैजिंग के लिए गए कर्ज पर चिंता जताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने कहा है कि उद्योग जगत को अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को खुद संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े उतार-चढ़ाव के समय विदेशी मुद्रा भंडार से पर्याप्त मदद नहीं मिलेगा। देश का विदेशी मुदा भंडार आज 330 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खान ने कहा, 'नियामक निश्चित तौर पर उद्योग को हर छोटे-मोटे जोखिम से नहीं बचा सकता है और इसलिए वाणिज्यिक निर्णय लेते समय उन्हें खुद विदेशी मुद्रा जोखिम का भी ध्यान रखना चाहिए।' रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले सप्ताह छह अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.2.2015)**

मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की सीमा में हो सकती है वृद्धि

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर आम बजट 2015-16 पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सरकार जनता खासकर मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए आयकर से छूट की सीमा में वृद्धि कर सकती है। ऐसा होने पर आम लोगों पर कर का बोझ कम होगा जिससे उनके पास बचत और खर्च करने के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा।

फिलहाल ढाई लाख रूपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं लगता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल साल 10 जुलाई को पेश हुए आम बजट 2014-15 में 60वर्ष के कम उम्र के व्यत्तियों के लिए व्यत्तिगत आयकर से छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी थी। इसी तरह उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर से छूट की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का एलान किया था। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज के एवज में कर छूट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल होम लोन पर सालाना दो लाख रुपये तक ब्याज चुकाने पर आयकर से छूट मिलती है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर से छूट की सीमा बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि निम्म आय वर्ग के करदाताओं की संख्या तो अधिक है लेकिन इनसे मिलने वाली कुल कर राशि कम है। लिहाजा सरकार अगर आयकर से छूट की सीमा बढ़ाती है तो राजस्व हानि उतनी अधिक नहीं होगी। इसके बजाय अधिकांश करदाताओं को राहत मिलेगा। प्रत्यक्ष कर सहिता के संशोधित विधेयक में भी आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की बात कही गई थी। इसी तरह संसद की वित्त मामलों संबंधी स्थायी समिति ने भी आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की सिफारिश की थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार मेक इन इंडिया अभियान को ध्यान में रखते उद्योग जगत पर भी कर का बोझ हल्का कर सकती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.2.2015)

बिहार में हरित क्रांति को बढ़ सकता है आवंटन

राजग सरकार आम बजट में बीमारू राज्यों को सौगात दे सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति के विस्तार के लिए बजट में धनराशि का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। वहीं आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए भी विशेष घोषणाएं की जा सकती हैं। इसी तरह वाराणसी और पटना सहित पूर्वांचल के शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भी धन आवंटन किया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा में हरित क्रांति के विस्तार पर जोर देने के लिए आम बजट में धनराशि आवंटित की जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फिलहाल इन सात राज्यों के करीब सवा सौ जिले लाभांवित है। हालाकि इसका आवंटन कम रहने की वजह से किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा, अधिकाधिक किसानों को इसका फायदा दिलाने के मकसद से इस योजना का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल 10 जुलाई को पेश राजग सरकार के बजट में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए दूसरी हरित क्रांति लाने की घोषणा की थी। सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्सेनिक की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए भी बजट में धनराशि का आवंटन बढ़ाकर चार हजार करोड़ रुपये से अधिक कर सकती है। राजग ने अपने पहले आम बजट में आर्सेनिक प्रभावित 20 हजार बस्तियों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सूत्रों का कहना है कि केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार और कोलकाता के शहरों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भी आम बजट में धनराशि का इजाफा कर सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.2.2015)

निवेश को बढ़ावा देगी राज्य सरकार

बिहार फाउंडेशन द्वारा 7 फरवरी को अधिवेशन भवन में आयोजित ग्लोबल मीट का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री एवं बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने किया।

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से प्रदेश में सरकार बनी तब से यहाँ तेजी से विकास और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए अच्छी औद्योगिक नीति लागू की गई है। निवेश और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं दी जा रही है। इसका लाभ प्रवासी बिहारियों को उठाना चाहिए। इससे पहले उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने कहा कि देश भर में बिहार सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति काफी लोकप्रिय है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर अबतक 8000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उन्होंने निवेशकों को आर्मंत्रित करते हुए कहा कि बिहार में निवेश के लिए आइए, सरकार मदद करने को तैयार है। यूएसए से आए उद्योगपति रवि वर्मा ने कहा कि बिहार में निवेश का बेहतर अवसर पैदा हुआ है। आइटी सेक्टर में निवेश से रोजगार बढ़ेंगे। उन्होंने वर्ष 2005 में कटिहार में आइटी कंपनी स्थापित की है, जो युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार उपलब्ध करा रही है। उनकी कंपनी जल्द ही यहाँ पर दूसरी यूनिट स्थापित करेगी। हांगकांग से पहुँचे उद्योगपति राजेश कुमार ने कहा कि बिहार की प्रतिभाओं की दुनिया में धूम है। प्रतिभाओं का पलायन रोकने हेतु नई योजनाओं पर कार्य करने की जरूरत है। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ .पी. साह ने कहा कि आइटी, फूड प्रोसेसिंग, होटल टूरिज्म एवं मेडिकल सर्विसेज आदि क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं, यहाँ रोजगार के लिए अवसर बढ़ेंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.2.2015)**

जीडीपी की तरह खुदरा महंगाई के आएंगे नए आंकड़े

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तरह सरकार खुदरा महंगाई के भी नए आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़े नए आधार वर्ष (2012) पर आधारित होंगे। साथ ही इनके आकलन का तरीका भी नया होगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ये आंकड़े जारी करेगा। सीएसओ ने हाल ही में जीडीपी की गणना का तरीका और आधार वर्ष बदला है जिसके बाद विकास दर में तेजी से उछाल आया है।

अब तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों का आधार वर्ष 2010 था। इसी के आधार पर सीएसओ जनवरी, 2011 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शहरी, ग्रामीण और दोनों क्षेत्रों के संयुक्त आंकड़े जारी कर रहा है। अब नए आधार वर्ष पर आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़े जनवरी 2015 के लिए जारी होंगे। आधार वर्ष बदलने के अलावा कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। मसलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश (वेटेज) 47.58 से घटकर 45.86 प्रतिशत होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.2.2015)**

मोदी का राज्यों को ज्यादा धन देने का वादा

राज्यों के साथ संपन्न हुई नीति आयोग की पहली बैठक में राज्यों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिक धन व लचीलेपन की मांग की। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की।

श्री मोदी ने निवेश चक्र को बहाल करने व अर्थव्यवस्था को तेज वृद्धि दर की राह पर लाने में राज्यों से सहयोग करने की अपील की।'सहकारी संघवाद' के नए काल का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्यों को ज्यादा धन दिए जाने के साथ राज्यों को योजनाएं संचालित करने के लिए ज्यादा अधिकार देने का वादा किया और उनसे कहा कि वे परियोजनाओं को लागू करने में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा 'निवेश चक्र, वृद्धि नौकरियों के सृजन और संपन्नता पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।' **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.2.2015)**

प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि पूर्ण घोषणा

1 जनवरी 2015 को एनआईटीआई आयोग के गठन की घोषणा पर केबिनेट के संकल्प से उद्धृत अंश
http//pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114268

Point 8e

भारत में 50 मिलियन से अधिक छोटे व्यापार हैं जो रोजगार जुटाने के मुख्य स्रोत हैं। ये व्यापार समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए अवसर जुटाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नीति निर्धारण में कौशल, ज्ञान उन्नयन और वित्तीय पूंजी और संबंधित प्रौद्योगिकी तत्व तक पहुंच बनाने के रूप में इस क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Point 6e

उद्यमशीलता, वैज्ञानिक और बौद्धिक मानव पूंजी का भारत का भंडार शक्ति का एक स्रोत है, जो सफलता की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए उपयोग किये जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वास्तव में 'सामाजिक पूंजी' जो हमारे लोगों में मौजूद है, अभी तक देश के विकास में बड़ा योगदान करता रहा है और इसलिए इसका उपयुक्त नीतिगत पहलों के माध्यम से लाभ उठाए जाने की जरूरत है।

हमें माननीय प्रधानमंत्री एवं उनकी सरकार से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की आशा करते हैं ताकि इस नीति का लाभ मिल सके।

छोटे व्यवसाय को फायनान्स - देश की उन्नति का ईंधन।

www.smallbusinessisbigbusiness.org

नॉन कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय हेतु औपचारिक वित्त के लिए एक्शन कमेटी

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.2.2015)

साइन बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएं

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के सभी दुकानदारों को अपने साइन बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। जो दुकानदार साइन बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग जल्द ही विशेष निरीक्षण अभियान चलाएगा। निरीक्षण अभियान के तहत विभाग के अधिकारी सबसे पहले उसी दुकान का निरीक्षण करेंगे, जिन्होंने दुकान के साइनबोर्ड पर विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं कराया है। (हिन्दुस्तान, 6.2.2015)

टैक्स नहीं देने वाले की परमिट पर रोक

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के सैकड़ों व्यापारियों के रोड परमिट पर रोक लगा दी है। कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जिनके बैंक खातों को विभाग ने सीज कर लिया है। ऐसे में सूबे के सैकड़ों व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

विभाग का कहना है कि इन व्यापारियों पर रोक इसलिए लगाया गया है, क्योंकि उनका लाखों रुपये टैक्स विभाग में बकाया है। विभाग ने ऐसे सभी व्यापारियों को जल्द बकाया टैक्स संबंधित अंचल में जमा कराने का निर्देश दिया है। बिना परमिट के सामान मंगवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.2.2015)**

बिहार सरकार

NB नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

सूचना

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के शहरी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि आर. ए. पी. डी. आर. पी. प्रोजेक्ट के अंर्तगत निर्गत विद्युत विपत्र का मुगतान ऑनलाइन वेब पोर्टल www.nbpdcl.co.in के instant payment option पर जाकर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पुराना उपभोक्ता सं. या CA Number डाल कर विद्युत विपत्र प्राप्त तथा भुगतान भी कर सकते हैं। 33 शहरों में आर. ए. पी. डी. आर. पी. प्रोजेक्ट को लागू करना है।

निम्नलिखित 19 शहरो में www.nbpdcl.co.in पोर्टल के द्वारा बिल का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है :-

हाजीपुर, महनार बाज़ार, सीतामढ़ी, बैरगेनिया, छपरा (शहरी), सोनपुर रिविलगंज, सिवान, गोपालगंज, बरौली, खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया, रामनगर, नरकटियागंज, ढाका, सुगौली।

अन्य 14 शहरों : मुजफ्फपुर, सहरसा, गोगरी जमालपुर, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, बेगुसराय, अररिया, फोरबीसगंज, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, बगहा, रक्सौल में इस वेबसाईट के द्वारा बिल का ऑनलाइन भुगतान नई बिलिंग सोफ्टवेयर के लागू होने के बाद की जा सकती है। आपकी सुविधा के लिए विद्युत विपत्र भुगतान का Use Manual पोर्टल पर उपलब्ध की गई है। ऑनलाइन भुगतान के दौरान तकनीकी समस्या एवं विद्युत विपत्र राशि के समायोजन से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए Ph. No. (7763815103,7763815132) अथवा email (emailid-revnuecell@gmail.com) पर संपर्क कर सकते है।

बिल संबंधित अन्य जानकारी हेतु स्थानीय विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अन्य शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता ऑनलाइन वेब पोर्टल northbiharbills.org पर अपना उपभोक्ता सं. डाल कर विद्युत विपत्र प्राप्त तथा भुगतान भी कर सकते है।

आदेशानुसार

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लिमिटेड पटना विजिलेंस मोबाईल हेल्पलाईन-18003456198

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.2.2015)

वोल्टेज फ्लैक्चुएशन से कब मिलेगी मुक्ति

बिहार में बिजली उत्पादन के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर राशि उपलब्ध कराती रही है। लेकिन सालों बाद भी यहाँ बिजली की हर जगह तक पहुंच और उसकी क्वालिटी का कोई अता-पता नहीं। क्वालिटी वाली बिजली का अर्थ है कि बिना वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के अनइनट्रप्टेड बिजली की सप्लाई। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली कंपनियां घाटा की बात बताकर बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। वहीं भारत में सबसे अधिक ट्रांसमिशन और टिस्ट्रीब्यूशन की लाइसेंस बिहार में है। फिर भी बिहार को अच्छी बिजली नसीब नहीं।

आय-व्यय की जांच हो : एक तरफ बिजली कम्पनी की ओर से बिजली की आपूर्ति पर अतिरिक्त खर्च की बात कह कर इसे बढ़ाने की बात कहा है तो दूसरी ओर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि राज्य सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि और बिजली कम्पनी की आय-व्यय के बारे में पूरी जांच की जानी चाहिए, पिछले दो दिनों की जनसुनवाई के बाद आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कुछ दिनों में इस पर बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन अपना फैसला सुनाएगी।

पिछले दो दिनों की जनसुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि सरकार से अनुदान तो मिलता रहता है लेकिन बिजली कंपनियाँ इसे सही से यूज नहीं कर पायी है। सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला लॉस है। कमीशन भी इसी पक्ष में है कि सरकार जब अनुदान दे रही है तो बिजली दर में बढ़ोतरी अव्यावहारिक होग्रा।

(साभार : आई नेक्स्ट, 6.2.2015)

बिजली कंपनी ने एजेंसियों को काम पूरा करने के लिए 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम

45 हजार से अधिक राजस्व गांवों को बिजली

बिहार के 45 हजार से अधिक राजस्व गांवों में तीन महीने के भीतर बिजली पहुँच जाएगी। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हो रहे विद्युतीकरण का काम हर हाल में मई तक पूरा कर लिया जाएगा। बिजली कंपनी ने 31 मई तक काम का क्लोजर रिपोर्ट एजेंसियों से मांगा है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) वर्ष 2005-06 में शुरू हुई। उस समय राज्य के 14 हजार गांवों में बिजली थी। आरजीजीवाई में केवल राजस्व गांवों के दस फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली देनी थी। 16, 25 या 40 किलोवाट क्षमता के ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने थे। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर बिहार के 11 जिलों के 5956 और दक्षिण बिहार के 14 जिले में 10 हजार 656 गांवों तक बिजली पहुंचानी थी। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बिहार के 15 जिले के 5177 और दक्षिण बिहार के तीन जिले के 699 गांवों का चयन हुआ। इस तरह दोनों योजनाओं में 22 हजार 488 गांवों तक बिजली पहुंचानी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काम दिसम्बर 2013 में पूरा हो गया लेकिन 11 वीं पंचवर्षीय योजनाओं का काम अब भी पूरा नहीं हो सका है। 24 जिलों के राजस्व गांवों तक बिजली पहुँचाने का जिम्मा पावरग्रिड को व एनएचपीसी को छह जिलों का जिम्मा दिया गया। बिजली कंपनी आठ जिले में काम कर रही है।

क्या है राजस्व गांव : वैधानिक मान्यता के अनुसार अंग्रेजी हुकुमत में जिन गावो को केंद्र मानकर राजस्व वसूली का काम हुआ। उसे राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। बिहार टेनेंसी एकट की धारा दो में भी इसका उल्लेख है। बिहार में अभी राजस्व गांवो की संख्या 45 हजार 103 है। हालांकि, बाद के वर्षों में गावों की संख्या बढ़ती गई पर सरकार ने इसे सोशल विलेज (सामाजिक गांव) माना।

सौ की आबादी वाले में काम : बिहार के 100 से अधिक आबादी वाले टोलों तक अभी बिजली पहुँचाई जा रही है। बिहार में 250 से अधिक आबादी वाले टोलों की संख्या 40 हजार 857 है। 100 से अधिक आबादी वाले टोले का कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। आकलन के अनुसार सौ से अधिक आबादी वाले तमाम गांवों की सख्या एक लाख से अधिक है। (हिन्दुस्तान, 12.2.2015)

अक्षय ऊर्जा में 200 अरब डॉलर का निवेश

बिजली, कोयला तथा अक्षय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि देश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 200 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है। कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हरित ऊर्जा क्षेत्र के पूरी तरह उपयोग करने के लिए कतार में खड़ी हैं।

गोयल ने कहा, कई कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताई है और कुल मिलाकर जितनी प्रतिबद्धता आई हैं, वह हमारे द्वारा निर्धारित मिशन से अधिक है।' उन्होंने कहा, 'हमारा जो लक्ष्य है, हम दोगुना करने कर विचार कर रहे हैं जो 200 अरब डॉलर के निवेश से 200 गीगावॉट या (2,00,000

मेगावॉट) से अधिक करना है।' सरकार का 2022 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 1,00,000 मेगावॉट पहुँचाने का लक्ष्य रखा है जो फिलहाल करीब 3,000 मेगावॉट है। गोयल ने कहा कि सरकार छतों पर सौर मॉडल पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, 'हम न केवल बड़े संयंत्रों पर ही गौर नहीं कर रहे हैं। छतों पर सौर संयंत्र लगाकर 40, 000 मेगावॉट बिजली पैदा करने की योजना है।' अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए राज्यों को जोड़ने के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं 7-8 राज्यों से बात कर रहा हूँ जहाँ काफी सौर ऊर्जा क्षमता है।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.2.2015)**

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संपत्ति कर वसूली जनवरी 2015 तक

• 1.98 होल्डिंग धारक हैं निगम क्षेत्र में • 18 लाख है निगम क्षेत्र की आबादी

	नूतन राजधानी अंचल	बांकीपुर अंचल	कंकड़बाग अंचल	पटना सिटी अंचल	कुल
कुल होल्डिंग	80137	34420	32414	50355	197326
रिटर्न फाईल	26791	11110	8137	13588	59626
वसूली	45379891	23065018	20049629	19573239	17178975

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.2.2015)

आरई इन्वेस्ट को उद्योग जगत का भारी समर्थन

भारत की ओर से अक्षय ऊर्जा पर आयोजित पहले वैश्विक सम्मेलन आरई-इन्वेस्ट 2015 की शुरूआत भारत के उद्योग जगत के नामी गिराभी प्रतिनिधियों, सरकार के प्रतिनिधियों और वित्त सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति में हुई। इसमें तब और उत्साह जुड़ गया जब प्रधानमंत्री ने कहा, 'अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत अब मेगावॉट से गीगावॉट की ओर बढ़ चुका है।'

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों ने घोषणा की कि वे हरित प्रतिबद्धता के तहत 2.9 गीगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र स्थापित करेंगी। यह भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता विस्तार पर खासा काम किया था और अब आरई इन्वेस्ट 2015 में उन्होंने व्यक्तिगत रुचि दिखाई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कह, 'वैश्वीकरण के दौर में हमारे पास ऊर्जा उत्पादन और संपर्क में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक देश के आखिरी पायदान पर बैठे हर परिवार तक बिजली नहीं पहुंचती, जब तक विकास आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.2.2015)**

विश्व बैंक की मदद से बनेगा जलमार्ग

गंगा जल मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग शुरू होने से समीप के इलाकों के कारोबार को बल मिलेगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटेगा। विश्व बैंक के सहयोग से इस कार्य योजना पर शीघ्र कार्य शुरू होगा। चार साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हल्दिया से इलाहाबाद तक जाएगा जहाज : राष्ट्रीय जल मार्ग-1 को व्यापार के लिए सुगम व सस्ता बनाएं जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके प्रथम चरण में हल्दिया से इलाहाबाद के बीच मार्ग को विकसित किया जाएगा। जल परिवहन मार्ग के लिए जरूरी आधारभूत संरचना, तकनीकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गायघाट स्थित राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान में इस मुद्दे पर वरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इसके बाद इस कार्य योजना को शुरू भी कर दिया गया है। इस योजना से व्यापार को नई राह जबकि रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.2.2015)

बिहार के छह लोग बने दिल्ली में विधायक

बिहार से जुड़े छह लोगों की जीत मिली है ये सभी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे 1. वंदना शर्मा, मुजफ्फरपुर, 2. पंकज पुष्कर 3. सौरभ भरद्वाज 4. संजीव झा, मधुबनी, 5. ऋतुराज गोविन्द्र, समस्तीपुर, 6. सोमनाथ भारती, नवादा

(साभार : प्रभात खबर, 11.2.2015)

निश्शक्त यात्रियों को रेलवे देगा पहचान पत्र

• रियायत के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने की पहल • रेलवे के अधिकृत डॉक्टर ही दे सकते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र • दो साल के लिए मान्य होगा रेलवे का पहचान पत्र। **(विस्तृत: दैनिक जागरण, 9.2.2015)**

50 वर्ष समस्याओं की समीक्षा संभव नहीं

पटना की 50 साल की समस्याओं की कोर्ट एक साथ समीक्षा नहीं कर सकता। पटना उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आवासीय प्लॉटों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका निरस्त कर दी।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 11.2.2015)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries Fortnightly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV (See Rule 8)

1.	Place of Publication	: Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaughary Marg, Patna - 800001
2.	Periodicity of its publication	: Fortnightly
3.	Printer 's Name	: A. K. Dubey
	Whether citizen of India? (if foreigner, state the Country of origin)	: Indian
	Address	: Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna - 800001
4.	Publisher's Name	: A. K. Dubey
	Whether citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin)	: Indian
	Address	: Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna - 800001
5.	Editor's Name	: Shri O. P. Tibrewal
	Whether citizen of India? (if foreigner, state the Country of origin)	: Indian
	Address	: N. M. Enterprises, Shri Ram Bhawan, Exhibition Road, Patna - 800001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and parterns of share holders	: Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna -800001

I, A. K. Dubey hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296